

ब्रिटेन के केवल 1 6 प्रतिशत लोग ट्रंप की राजनीति से सहमत हैं

बाकी जनता ट्रंप के तौर-तरीके व सोच से असहमत और सख्त खिलाफ हैं

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17, सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मंगलवार को ब्रिटेन की राजकीय यात्रा के दौरान भले ही शान-ओ-शौकत का आनंद ले रहे हों, लेकिन असल में वे एक तरह के बुलबुले में हैं, ब्रिटिश जनता से काफी दूर, जो राजधानी लंदन और देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई है, इस सजे संवरे और बड़ी सावधानी पूर्वक आयोजित कार्यक्रम के प्रति अपनी नाराज़गी और निंदा जाहिर करने के लिए।

ब्रिटिश लोग छोटी, आकर्षक, तीखी और संक्षिप्त टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं। लंदन में एक में एक हाईप्रोफाइल विरोध मार्च के पोस्टरों पर लिखा नारा, “डैप ट्रंप” (ट्रंप को हटाओ) नारा जनता की भवना और अमेरिकी राष्ट्रपति की राजनीति के प्रति उसके गुस्से को दिखाने के लिए काफी था।

यात्रा से कुछ समय पहले हुए एक जनमत सर्वेक्षण में पता चला कि केवल 16 प्रतिशत ब्रिटिश जनता ट्रंप से सहमत है। बाकी लोग हल्की नापसंदगी से लेकर बेहद कड़ी नफ़रत तक, अलग-अलग तरीकों से उनकी राजनीति को दुकरा रहे हैं। इन भावनाओं का इज़हार जगह-जगह हो रही सभाओं और प्रदर्शनों में हो रहा है। एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता ने तो ट्रंप के सम्मान में विंडसर पैलेस में होने

■ इस जनभावना से इंगलैण्ड की सरकार अनभिज्ञ नहीं है, इसीलिए ट्रंप की ब्रिटेन की यात्रा को जनता से दूर विंडसर पैलेस में रखा गया है। पूरे शान-शौकत व आनंदमयी वातावरण में तथा ट्रंप से राजनीतिक काम की बातचीत भी अगले दिन, ब्रिटेन के प्र.मंत्री के फार्म हाउस पर आयोजित की गई है।

■ दूसरी ओर, लंदन में जनता गंदे व भद्दे नारे लगा रही है और प्रदर्शन कर रही है, ब्रिटेन की सरकार व ट्रंप के खिलाफ। नारों का सार है कि इंगलैण्ड की सरकार कुछ तो रीढ़ की हड्डी में दम दिखाये व साफ़्तांग न हो, ट्रंप के सामने, ट्रंप को अच्छे मूड में रखने के लिए, ट्रंप को लुभाने के लिए।

■ मोदी के जन्म दिन पर, पुतिन ने भरपूर बधाई दी तथा यह जताने का प्रयास किया कि अमेरिका का रूस को अलग-थलग करने का प्रयास सफल नहीं हो रहा, बल्कि सभी जगह, चीन में भी एस.सी.ओ. सम्मेलन में वो सादर आमंत्रित हैं।

■ भारत को भी सभी तरफ से यूरोप से भी पूर्ण मित्रता व समर्थन मिल रहा है, ट्रंप द्वारा भारत के मामले में अनुचित टैरिफ लगाने के कारण।

■ ट्रंप इंगलैण्ड की सरकार के भव्य आतिथ्य की खुमारी लगभग सुखद निद्रा में हैं, तथा उनकी “चतुर राजनीति” का खामियाजा यूक्रेन उठा रहा है, क्योंकि रूस की लगातार बढ़ती व प्रखर होती बमबारी से सैकड़ों यूक्रेनवासी प्रतिदिन मारे जा रहे हैं।

वाले भोज का निमंत्रण ही दुकरा दिया। दूसरी तरफ, कुछ प्रदर्शनकारियों ने विंडसर पैलेस की दीवारों पर ट्रंप की तस्वीर को कुख्यात जेफ्री एप्स्टीन के साथ प्रदर्शित किया।

लंदन की सड़कों पर भारी भीड़ विरोध मार्च कर रही थी। कुछ प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सरकार से अपील कर रहे थे कि वह साहस दिखाए और ट्रंप को खुशामद करने के लिए इतना नीचे न गिरे।

निश्चित ही, ब्रिटिश सरकार और

सुरक्षा तंत्र जनता की भावनाओं से पूरी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए पूरी यात्रा को जनता से दूर रखने और महल की कड़ी सुरक्षा वाली दीवारों के अंदर रखने के लिए हर संभव सावधानी बरती गई। यहां तक कि राजनीतिक बैठक भी लंदन तथा अन्य लोकप्रिय स्थानों से दूर, प्रधानमंत्री के कंठी होम में आयोजित की गई।

जब ब्रिटिश सरकार ट्रंप को राजसी ठाठ-बाट और परंपरागत स्वागत से “सम्मोहित” करने का नाटक कर रही थी, उसी दौरान असली राजनीति दुनिया

के अन्य हिस्सों में चल रही थी।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की उस मुख्य रेलवे लाइन पर भयंकर हमला करने का आदेश दिया, जो देश को पश्चिमी यूरोप से जोड़ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बार-बार की अपीलों को अनदेखा करते हुए, रूस, यूक्रेन पर बेरहमी हमले कर रहा है।

कठोर कूटनीति के खिलाड़ी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने “मित्र” प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीकानेर में पूर्व पार्षद तथा व्यापारी के 6 ठिकानों पर ईडी की रेड

बीकानेर, 17 सितम्बर (निस)। यहां फिलिस्तीन का समर्थन करने और विदेशी फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। जयपुर से आई ईडी की टीम ने छह ठिकानों पर

■ पूर्व पार्षद जावेद खान के सुभाषपुरा स्थित मकान तथा व्यापारी मोहम्मद सादिक के फड़ बाजार स्थित घर पर ईडी की टीम ने पूछताछ की।

छापा मारा है। इसमें पूर्व पार्षद और एक व्यापारी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईडी को बीकानेर से फिलिस्तीन के समर्थन और विदेशी फंडिंग का इनपुट मिला था। कार्रवाई के लिए ईडी की टीम जयपुर से यहां मंगलवार को ही पहुंच गई थी। इसके बाद बुधवार सुबह आठ बजे टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर आरपीएफ के जवान भी तैनात

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘पराली जलाने पर कुछ किसानों को जेल भेजना, दूसरों के लिए कठोर संदेश हो सकता है’

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 सितम्बरा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पराली जलाने के लिए कुछ किसानों को जेल भेजने से दूसरों को एक सख्त संदेश जा सकता है और यह दूसरों के लिए एक निवारक (डिटैरेंट) की तरह काम कर सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी, हर अक्टूबर में दिल्ली-एनसीआर की दमघोंदू वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की।

इससे पहले, “एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) अपराजिता सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ को बताया कि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों को सब्सिडी और उपकरण मुहैया कराए गए हैं।

उन्होंने कहा, “लेकिन किसानों की वही कहानी रहती है। पिछली बार किसानों ने कहा था कि उन्हें उस समय पराली जलाने को कहा गया था, जब उपग्रह उस

‘प्र.मंत्री की मां का एआई वीडियो हटाए कांग्रेस’

पटना, 17 सितंबर। बिहार चुनाव से पहले पटना हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस के उस एआई वीडियो, जिसमें पीएम मोदी और उनकी माँ को दिखाया गया था, को हटाने का निर्देश दिया है। हाई

■ पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया कि यह वीडियो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए।

कोर्ट ने अब इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस ने बीते दिनों पीएम मोदी और उनकी मां (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे किसानों को पराली जलाने से रोका जा सकता है

■ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में हर साल अक्टूबर में गंभीर वायु प्रदूषण होने के संबंध में दापर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसानों की गिरफ्तारी रूटीन में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ संदेश देने के लिए ही ऐसा किया जाना चाहिए।

■ चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, किसान हमारे लिए खास हैं, उनकी वजह से हमें भोजन मिलता है। पर, इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसका अनुचित लाभ उठाएं।

■ ज्ञातव्य है कि अक्टूबर महीने में हरियाणा और पंजाब के किसान खेतों में पराली जलाते हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर में हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है।

क्षेत्र से नहीं गुजर रहा था। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई विस्तृत आदेश पारित

किए हैं, और फिर भी हर बार किसान केवल लाचारी ही जताते हैं।”

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या अमेरिका , भारत से संबंधों को “ सामान्य ’ करने के बारे में वास्तव में गंभीर है?

मोदी को जन्म दिन पर, ट्रंप द्वारा बधाई का फोन करना, क्या ठोस प्रगति है?

-सुकुमार शाह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17, सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भेजी गई शुभकामनाएं केवल औपचारिकता नहीं थीं, बल्कि उन अवरूद्ध व्यापार वार्ताओं में नए उत्साह का संकेत थीं, जो कठोर अमेरिकी टैरिफ के कारण रुक गई थीं। दोनों नेताओं के बीच यह गर्मजोशी ऐसे समय में आई है जब महीनों बाद पहली बार दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को स्थिर मार्ग पर लाने का गंभीर प्रयास शुरू हुआ है।

इस सार्वजनिक सद्भावना के साथ एक ठोस प्रगति भी हुई। पहली बार, कठोर टैरिफ उपायों, जैसे भारतीय

■ शायद इस बार ठोस प्रगति के संकेत से तो लगते हैं, क्योंकि दोनों ने लम्बे समय से लटकते हुए व्यापारिक समझौते की वार्ता के कई दौर के बाद यह तो महसूस कर लिया है कि लम्बा लटकाने से किसी को फायदा नहीं। इससे केवल माहौल विषाक्त ही होता है।

■ अतः, नये टैरिफ के बाद, दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गये थे कि अब तो बातचीत की खबरें आना ही बंद सा हो गया था।

■ पर, अब अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का ट्रंप के फोन के बाद, बातचीत के लिए वापस भारत आना, यह संकेत तो है ही कि दोनों देशों के समझौते के बारे में इतने गंभीर प्रयास पहले नहीं हुए थे।

आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क और रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत लेवी के बाद, दोनों देशों के व्यापार वार्ताकार

मंगलवार को आमने-सामने बैठे। अमेरिकी अधिकारियों ने इन चर्चाओं को “सकारात्मक” बताया, जबकि नई

दिल्ली में इसे एक अहम शुरुआत माना गया, जो यह संकेत देता है कि दोनों पक्ष अब गिरते संबंधों को संभालने और साझा

समाधान तलाशने के लिए इच्छुक है।

यह प्रगति ऐसे समय में आई है जब वॉशिंगटन से सख्त बयानबाजी सामने आ रही थी। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत अमेरिकी कॉर्न की खरीद नहीं बढ़ाता, तो उसे अमेरिकी बाजारों तक पहुंच खोने का खतरा हो सकता है। ऐसे में अचानक रुख का नरम होना यह दर्शाता है कि भले ही दोनों देशों की स्थिति मजबूत हो, फिर भी यह मान्यता बन रही है कि लंबे समय तक टकराव दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के हित में नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सहयोगी दलों की बढ़ती मांगों से एडजस्ट नहीं कर पा रही है भाजपा बिहार में

भाजपा के रणनीतिकारों ने निजी तौर पर माना कि सहयोगियों की मांग मानी तो पार्टी कमज़ोर हो जाएगी

■ जद (यू) और भाजपा के बीच भी सीटों के मुद्दे पर तनाव है। इसका संकेत तब मिला जब सीटों पर चर्चा के लिए नड्डा पटना आए, पर उन्हें नीतीश से बिना मिले लौटना पड़ा।

■ छोटे दलों की भी मांगें बड़ी-बड़ी हैं। चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं। जीतनराम मांझी 20 सीटें, तो उपेन्द्र कुशवाहा की मांग भी 15 सीटों की है। पर, भाजपा इन दलों को इनकी मांग से आधी सीटें ही देना चाहती है।

विश्लेषकों के अनुसार, यह संवादहीनता एनडीए के दो मुख्य स्तंभों के बीच भरोसे की कमी का स्पष्ट संकेत है। खास बात यह है कि दोनों दलों के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है।

तनाव को और बढ़ाते हुए, चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी के लिए 40 सीटों की मांग की है, जबकि जीतन राम मांझी 20 सीटों से कम पर राजी नहीं हैं। दोनों नेताओं ने यह संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगों समय पर पूरी नहीं हुई, तो वे गठबंधन में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार कर सकते हैं। तीसरे छोटे सहयोगी, उपेन्द्र कुशवाहा को अनौपचारिक रूप से 10 सीटों की पेशकश की जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी ने इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं दी है।

भाजपा के रणनीतिकार निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि सहयोगियों को इतनी अधिक सीटें देना राज्य में पार्टी

की अपनी स्थिति को कमजोर कर सकता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि एक संभावित समझौता फार्मूला पर विचार किया जा रहा है, जिसमें एलजेपी को 20, एचएएम को 10, और कुशवाहा की पार्टी को 10 सीटें दी जा सकती हैं, हालांकि यह प्रस्ताव सहयोगियों की मांगों से काफी कम है।

सीट बंटवारे में देरी एक रणनीतिक कदम भी मानी जा रही है। एनडीए के नेता इंडिया गठबंधन पर नजर रखे हुए हैं, जो जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाला है। एनडीए इस इंतज़ार में है कि वह अपनी सीटें विपक्षी रणनीति के हिसाब से समायोजित कर सके।

लेकिन, सहयोगी खुलेआम धमकी दे रहे हैं और भाजपा ने अभी तक नीतीश कुमार से सीधी बातचीत नहीं की है, यह गतिरोध एनडीए की कमजोर एकता को उजागर करता है। अगर जल्द

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ने ट्रंप को 3 7 मिनट से हराया फोन काल की प्रतिस्पर्धा में

“शो मैन” ट्रंप पूर्णतया वाकिफ हैं, “पहले मारे वो मीर” के सिद्धांत से

■ भारत-पाक युद्ध में, उदाहरण के लिए, ट्रंप ने “सीजफायर” करवाने का श्रेय लेने के लिए, सबसे पहले सोशल मीडिया पर खबर चलवा दी। और इसका फायदा वे अंत तक लेते रहे, चाहे भारत ने उच्चतम स्तर पर इस खबर का कई बार खंडन किया।

■ ऐसा ही, तेहरान व तेल अवीव के युद्ध के दौरान भी ट्रंप ने करवाया।

■ पर, इस बार ट्रंप नहीं कर पाये, मोदी की जन्म दिन की बधाई के “फोन कॉल” के बारे में।

■ मोदी ने बधाई के फोन की खबर 10:53 पर, सोशल मीडिया पर डाली। पर, ट्रंप ऐसा 11:30 बजे ही कर पाये।

■ इस “हार” से ट्रंप काफी असहज हो गए, क्योंकि वे सदा घटनाक्रम पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, जो पहले खबर देने से स्थापित होता है।

यह कॉल इसलिए भी अहम है, क्योंकि भारत ने कई मुद्दों पर अमेरिका का साथ देने से इनकार किया – जैसे कि “ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर” के लिए

ट्रंप को जिम्मेदार मानना (जबकि वे नहीं थे), उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समर्थन देना, और टैरिफ विवाद आदि।

इन सब बातों ने उस रिश्ते पर गहरा असर डाला, जिसे ज़्यादातर विश्लेषक “दुनिया की नहीं तो, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक” मानते हैं। इसका अंत तब दिखा, जब डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था – जो कि जीडीपी के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है – को “मरी हुई” बता दिया था।

इसलिए ट्रंप का यह फोन कॉल बेहद अहम था, लेकिन इस कहानी में और भी कुछ है।

शायद सबसे महत्वपूर्ण बात बातचीत में नहीं, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के समय में थी, एक तरह की ‘वीडू’, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को 37 मिनट से हरा दिया।

प्रधानमंत्री मोदी की एक्स पर पोस्ट रात 10:53 बजे आई। ट्रंप की पोस्ट दृथ सोशल पर रात 11:30 बजे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईवीएम पर उम्मीदवारों के रंगीन फोटो दिखेंगे

नयी दिल्ली, 17 सितंबर। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इसी साल कराये जाने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर लगाये जाने वाले मतपत्रों पर उम्मीदवारों के

■ चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत कर रहा है उसके बाद पूरे भारत में ऐसा ही होगा।

नाम के साथ उनकी रंगीन तस्वीरें भी रखेगा।

भविष्य में अन्य विधानसभा चुनावों और आम चुनाव में भी ईवीएम मतपत्रों में ये संशोधन दिखेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)